



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]
No. 19]नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2000/फाल्गुन 4, 1921
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2000/PHALGUNA 4, 1921

महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2000

सं. टीएमपी/10/2000-सामान्य.—महापत्रन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार पट्टा हस्तांतरण शुल्क/बंधक शुल्क के संबंध में आदेश पारित करता है।

मामला सं. टीएमपी/10/2000-सामान्य

आदेश

(फरवरी, 2000 के चौथे दिन को पारित किया गया)

पट्टाधारकों द्वारा पट्टाधारण अधिकारों को बंधक रखने संबंधी अनुमति के लिए हस्तांतरण शुल्क/बंधक शुल्क लगाने के लिए विभिन्न पत्रन न्यासों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इस मामले की कानूनी दृष्टि से जांच-पढ़ताल की गई थी। यह पाया गया था कि पट्टाधारण अधिकारों को बंधक रखने के संबंध में महापत्रन न्यास अधिनियम में विशेष रूप में परिकल्पना नहीं की गई थी। इसे देखते हुए, यह प्राधिकरण ऐसे बंधकनामों के लिए कोई शुल्क लगाने को कानूनी रूप में अनुमोदित नहीं कर सकता। वस्तुतः, विधान में ऐसा विशिष्ट प्रावधान न होने के कारण, सरकार भी इसके लिए प्राधिकृत नहीं कर सकती।

2. सभी महापत्रों को यह कानूनी स्थिति, सूचना और आवश्यक कारबाई हेतु प्राधिकरण के दिनांक 4 फरवरी, 99 के पत्र संख्या टीएमपी/2/98-टीपीटी द्वारा सूचित कर दी गई थी। इस पत्र के बावजूद भी, ऐसे प्रस्ताव लगातार प्राप्त होते रहे हैं। इससे पता चलता है कि उक्त पत्र में स्पष्ट की गई स्थिति को सभी पत्रन न्यासों ने स्वीकार नहीं किया है और संभवतः पट्टाधारण अधिकारों के हस्तांतरण/बंधक रखने के लिए अनुमति प्रदान करने पर शुल्क बसूल कर रहे हैं।

3. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और समग्र ध्यान देने के पश्चात् एतद्वारा यह औपचारिक आदेश दिया जाता है कि महापत्रन न्यास अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान न होने के कारण पट्टाधारण अधिकारों के हस्तांतरण/बंधक रखने के लिए अनुमति प्रदान करने पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता और इस प्राधिकरण के पास कोई ऐसा शुल्क लगाया जाने के लिए अनुमोदन प्रदान करने संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है।

4. सभी पत्तन न्यासों को भविष्य में तदनुसार कार्रवाई करने के लिए और जहां आवश्यक हो, अपने दरों के मान में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए एतद्वारा निर्देश दिया जाता है। यह आदेश भारत के राजपत्र में इसको अधिसूचित किए जाने के तत्काल बाद प्रभावी हो जाएगा।

एस. सत्यम्, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2000

No. TAMP/10/2000-Genl.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby passes an order relating to lease transfer fee/mortgage fee as in the Order appended hereto

CASE No. TAMP/10/2000-Genl.

ORDER

(Passed on this 4th day of February, 2000)

Proposals had been received from different Port Trusts for approval of levy of transfer fee/mortgage fee for permitting mortgage of leasehold rights by lessees. The matter was examined from the legal point of view. It was found that mortgage of leasehold rights was not specifically envisaged in the Major Port Trusts Act. That being so, this Authority could not legally approve levy of any fee for such mortgages. In fact, in the absence of any specific enabling provision in the Statute, even the Government could not authorise it.

2. This legal position was intimated to all the Port Trusts vide this Authority's communication No. TAMP/2/98-TPT dated 4 January, 99 for information and appropriate action. This communication notwithstanding, such proposals continue to be received. This suggests, the Port Trusts have not accepted the position explained in the said communication and are, possibly, continuing to charge fees for permitting transfer/mortgage of leasehold rights.

3. Taking this position into account, and after a collective application of mind, it is hereby formally ordered that, in the absence of a specific provision therefor in the Major Port Trusts Act, there can be no levy of fee for permitting transfer/mortgage of leasehold rights, and, this Authority does not have the jurisdiction to accord approval for levy of any such fees.

4. All the Port Trusts are hereby directed to take action accordingly in future and, introduce appropriate changes in their Scale of Rates where necessary. This Order will come into effect immediately after its notification in the Gazette of India.

S. SATHYAM, CHAIRMAN

[Advt/III/IV/Exty/143/99]